VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(04 December 2024)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- ब्रिक्स देशों की 'डी-डॉलराइजेशन' योजना पर डोनाल्ड ट्रम्प की 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी
- भारत सरकार द्वारा GDP आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 किया जायेगा
- दुनिया भर में 'भूमि क्षरण' से मानवता को जीवित रखने की पृथ्वी की क्षमता को खतरा
- MCQs

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

ब्रिक्स देशों की 'डी-डॉलराइजेशन' योजना पर डोनाल्ड ट्रम्प की 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी:

मामला क्या है?

- हाल फ़िलहाल में डोनाल्ड ट्रंप की सबसे साहसिक घोषणाओं में से एक भारत सहित ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी है, जो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एक आम ब्रिक्स मुद्रा पर विचार करता रहा है।
- डोनाल्ड ट्रम्प की यह टिप्पणी ब्रिक्स देशों के बीच उस चर्चा के जवाब में आई है, जिसमें ये देश व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की संभावना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अक्टूबर में रूस में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में स्थानीय मुद्रा लेनदेन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, एक ऐसा कदम जिसे ट्रंप ने अब चुनौती देने की कसम खाई है।
- उल्लेखनीय है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ब्रेटन वुड्स समझौते (1944) ने अमेरिकी डॉलर को वैश्विक वित्तीय प्रणाली की आधारशिला के रूप में स्थापित

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

किया। इस प्रणाली ने डॉलर को सोने से और अन्य मुद्राओं को डॉलर से जोड़ा, जिससे स्थिरता सुनिश्चित हुई और डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बनाया गया। हालांकि 1971 में सोने का मानक समाप्त हो गया, लेकिन डॉलर ने वित्तीय प्रणाली और विश्वसनीयता में अपनी गहरी भूमिका के कारण अपना वैश्विक प्रभुत्व बनाए रखा।

ट्रंप की टैरिफ धमकियां भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए खतरा?

- डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियां भारत के लिए विशेष रूप से चिंताजनक हैं, जो अमेरिका के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध बनाए रखता है।
- अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2023-24 में 120 अरब डॉलर को पार कर गया है। अमेरिका को भारत का निर्यात पोर्टफोलियो विविध है, जिसमें कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान और आईटी सेवाएं शामिल हैं।
- ऐसे में डॉलर को कमजोर करने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का ट्रंप का वादा भारतीय निर्यातकों के लिए उच्च लागत का कारण बन सकता है, जिससे उनके उत्पाद अमेरिकी बाजार में कम प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे।

- उल्लेखनीय है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि डी-डॉलराइजेशन भारत की आर्थिक नीति या रणनीति का हिस्सा नहीं है इसके बावजूद, इस मामले पर डोनाल्ड ट्रम्प का कड़ा रुख भारत को मुश्किल स्थिति में डाल सकते हैं, जिससे देश को अमेरिकी मांगों का पालन करने या उच्च टैरिफ के परिणामों का सामना करने के बीच चयन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

ब्रिक्स और डॉलर: एक बढ़ती चुनौती

- ब्रिक्स देशों ने लंबे समय से गैर-डॉलर लेनदेन बढ़ाने पर चर्चा की है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिया है कि समूह बेल्जियम-आधारित स्विफ्ट वित्तीय प्रणाली के विकल्प तलाश रहा है।
- ध्यातव्य है कि अक्टूबर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, बैंकिंग नेटवर्क को मजबूत करने और ब्रिक्स सदस्यों के बीच स्थानीय मुद्रा निपटान को सुविधाजनक बनाने के लिए एक संयुक्त घोषणा की गई थी।
- हालांकि, अमेरिकी डॉलर का कोई निश्चित विकल्प प्रस्तावित नहीं किया गया है, और वैश्विक व्यापार में डॉलर को बदलने का विचार एक दूर की संभावना बनी हुई है।

- उल्लेखनीय है कि टैरिफ लगाने की ट्रम्प की धमकी डी-डॉलरीकरण के इस बढ़ते प्रयास से उपजी है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर भारत जैसे देश डॉलर से दूर चले जाते हैं तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा।

ब्रिक्स समूह अमेरिकी डॉलर को चुनौती क्यों देना चाहता है?

- ब्रिक्स राष्ट्र 21वीं सदी में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से हैं। वे अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के इच्छुक हैं, जो दुनिया की आरक्षित मुद्रा है, जिसका उपयोग वैश्विक व्यापार के लगभग 80% के लिए किया जाता है।
- अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि डॉलर-प्रधान वित्तीय प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रमुख आर्थिक लाभ देती है, जिसमें कम उधार लागत, बड़े राजकोषीय घाटे को बनाए रखने की क्षमता और विनिमय दर स्थिरता आदि शामिल हैं।
- अमेरिका तथाकथित डॉलरीकरण से विशाल भू-राजनीतिक प्रभाव से भी लाभान्वित होता है, जिसमें अन्य देशों पर प्रतिबंध लगाने और व्यापार और पूंजी तक उनकी पहुँच को प्रतिबंधित करने की क्षमता शामिल है।
- ब्रिक्स राष्ट्रों ने अमेरिका पर डॉलर को "हथियार" बनाने का आरोप लगाया है।
- अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण प्रतिबंध लगाए जाने के बाद एक नई संयुक्त मुद्रा के बारे में चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

ब्रिक्स मुद्रा योजना कैसे विकसित हुई है?

- ब्रिक्स मुद्रा के विकास की बात सबसे पहले 2008/9 के वित्तीय संकट के तुरंत बाद की गई थी, जब अमेरिका में रियल एस्टेट में उछाल और खराब विनियमन ने पूरी वैश्विक बैंकिंग प्रणाली को लगभग ध्वस्त कर दिया था।
- पिछले साल दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, ब्रिक्स ने डॉलर से संबंधित जोखिमों के जोखिम को कम करने के लिए एक आम मुद्रा बनाने की संभावनाओं का अध्ययन करने पर सहमति व्यक्त की, हालांकि ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि इसे सफल होने में कई साल लग सकते हैं।
- इस वर्ष अक्टूबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कजान में हालिया ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान एक और कदम आगे बढ़ाया, जिसमें पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए डिज़ाइन की गई ब्लॉकचेन-आधारित अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया।
- उल्लेखनीय है कि रूस और ब्राजील नई मुद्रा के सबसे मजबूत समर्थक हैं। जबकि चीन ने स्पष्ट रूप से कोई विचार व्यक्त नहीं किया है, हालांकि चीन ने डॉलर पर निर्भरता कम करने की पहल का समर्थन किया है। इस बीच, भारत इस विचार को लेकर काफी सतर्क है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

क्या डोनाल्ड ट्रम्प की 100% टैरिफ़ धमकी बहुत जल्दबाजी है?

- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में कुछ हद तक जल्दबाजी कर रहे हैं क्योंकि ब्रिक्स नेताओं की बयानबाजी के बावजूद मुद्रा प्रस्ताव में बहुत कम प्रगति हुई है।
- वास्तव में 2 दिसंबर को, दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स मुद्रा बनाने की कोई योजना नहीं है, उन्होंने "हाल ही में गलत रिपोर्टिंग" को गलत बयान फैलाने के लिए दोषी ठहराया।
- साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप की यह धमकी अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में ब्रिक्स देशों के साथ संबंधों को खराब कर सकती है, जो अमेरिका के कुछ प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं। यह जवाबी कार्रवाई के खतरे को भी जन्म दे सकता है।
- हालांकि रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि रिजर्व मुद्रा के रूप में डॉलर के मुकाबले एक प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, उन्होंने कहा कि "अधिक से अधिक देश अपने व्यापार और विदेशी आर्थिक गतिविधियों में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग की ओर बढ़ रहे हैं"।

भारत सरकार द्वारा GDP आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 किया जायेगा:

चर्चा में क्यों है?

- भारत सरकार सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की गणना के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से 2022-23 तक अद्यतन करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य देश की आर्थिक संरचना का अधिक सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। यह अद्यतन एक दशक से अधिक समय में पहला है, अंतिम संशोधन 2011-12 में किया गया था।
- इस परिवर्तन की देखरेख के लिए, बिस्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में 26 सदस्यीय 'राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति (ACNAS)' को नए डेटा स्रोतों की पहचान करने और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी संकलन के लिए कार्यप्रणाली को परिष्कृत करने का काम सौंपा गया है। इस समिति द्वारा 2026 की शुरुआत तक संशोधन पूरा करने की उम्मीद है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

GDP का आधार वर्ष क्या होता है?

- आधार वर्ष मुद्रास्फीति के प्रभावों को समाप्त करके GDP की गणना करने के लिए एक बेंचमार्क है, जिससे समय के साथ आर्थिक विकास की तुलना की जा सकती है। आधार वर्ष को अपडेट करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि GDP डेटा नवीनतम आर्थिक गतिविधियों, उपभोग पैटर्न और उद्योग के योगदान को दर्शाता है।
- 2011-12 से 2022-23 में बदलाव विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि पिछले एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव हुए हैं। नए क्षेत्र उभरे हैं, डिजिटलीकरण में तेजी आई है और अर्थव्यवस्था ने महामारी के बाद की वास्तविकताओं के अनुकूल खुद को ढाल लिया है।

GDP आधार वर्ष में संशोधन की आवश्यकता क्यों है?

- GDP आधार वर्ष संशोधन सटीक आर्थिक डेटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप है। आदर्श रूप से, अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए आधार वर्ष को हर पाँच साल में संशोधित किया जाना चाहिए।
- GDP के आधार वर्ष के नियमित अपडेट अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों, जिसमें उपभोग पैटर्न में बदलाव, क्षेत्रीय योगदान और उभरते क्षेत्रों को सटीक रूप से दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण है, शामिल करना शामिल है।

- GDP का आधार वर्ष विभिन्न वर्षों में आर्थिक आंकड़ों की तुलना करने के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह क्रय शक्ति में बदलाव को समझने में मदद करता है और मुद्रास्फीति के लिए समायोजित विकास के आंकड़ों की गणना करने में सक्षम बनाता है।
- 2022-23 की आर्थिक वास्तविकताओं के साथ संरेखित करके, संशोधित श्रृंखला नीति निर्माण और विश्लेषण के लिए अधिक सटीक रूपरेखा प्रदान करेगी।

GDP के आधार वर्ष में संशोधन के कारण:

- **संरचनात्मक परिवर्तन को प्रतिबिंबित करना:** भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवाओं और प्रौद्योगिकी की ओर महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। पुराना आधार वर्ष इन तेजी से बढ़ते क्षेत्रों के योगदान को पर्याप्त रूप से दर्शाने में सक्षम नहीं हो सकता है।
- **नये डेटा स्रोतों को शामिल करना:** 2011-12 से, डिजिटल भुगतान सांख्यिकी, ई-कॉमर्स मैट्रिक्स और वास्तविक समय व्यापार डेटा जैसे उच्च आवृत्ति डेटा की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। ये स्रोत GDP गणना के लिए अधिक सटीक इनपुट प्रदान करेंगे।
- **महामारी के बाद का आर्थिक परिदृश्य:** कोविड-19 महामारी ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक गतिशीलता को नया आकार दिया है। 2022-23 को आधार वर्ष के रूप में

उपयोग करके, सरकार का लक्ष्य इन परिवर्तनों को शामिल करना और आर्थिक सुधार का अधिक सटीक आकलन प्रदान करना है।

- **अंतर्राष्ट्रीय तुलना:** आधार वर्ष को अद्यतन करने से भारत की GDP गणना पद्धतियां अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो जाएंगी, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ संगतता और तुलनीयता सुनिश्चित होगी।

आधार वर्ष परिवर्तन के निहितार्थ:

- **संशोधित वृद्धि अनुमान:** इस बदलाव से संभवतः पिछली GDP वृद्धि दरों में संशोधन होगा, जिससे आर्थिक रुझानों की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। इससे कुछ वर्षों में तेज या धीमी वृद्धि का पता चल सकता है, जिससे नीति मूल्यांकन प्रभावित हो सकता है।
- **नीति निर्माण:** अधिक सटीक GDP आंकड़े सरकार को लक्षित आर्थिक नीतियां तैयार करने में सहायता करते हैं, विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में।
- **निवेशकों में विश्वास:** पारदर्शी और अद्यतन आर्थिक आंकड़े निवेशकों का विश्वास बढ़ाते हैं, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

दुनिया भर में 'भूमि क्षरण' से मानवता को जीवित रखने की पृथ्वी की क्षमता को खतरा:

चर्चा में क्यों है?

- संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट, 'स्टेपिंग बैक फ्रॉम द प्रीसिपिस: ट्रांसफॉर्मिंग लैंड मैनेजमेंट टू स्टे इन द प्लेनेटरी बाउंड्री', में पाया गया है कि भूमि क्षरण की समस्या पृथ्वी की मानवता को बनाए रखने की क्षमता को कम कर रहा है, और इसे उलटने में विफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए चुनौतियां खड़ी करेगी।
- उल्लेखनीय है कि यह अध्ययन 'मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD)' द्वारा जर्मनी के पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च के सहयोग से किया गया है। यह अध्ययन 2 दिसंबर, सऊदी अरब के रियाद में UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (COP16) के 16वें सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले, को प्रकाशित हुआ था।

भूमि क्षरण क्या होता है?

- UNCCD के अनुसार, भूमि क्षरण की परिघटना वर्षा सिंचित फसल भूमि, सिंचित फसल भूमि, या रेंज, चारागाह, वन और वुडलैंड्स की जैविक या आर्थिक उत्पादकता और जटिलता में कमी या हानि को दर्शाता है, जो भूमि उपयोग और प्रबंधन प्रथाओं सहित दबावों के संयोजन के परिणामस्वरूप होती है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार हर साल दस लाख वर्ग किलोमीटर भूमि का क्षरण हो रहा है, और अनुमान है कि 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर भूमि क्षरण से पहले से प्रभावित हो चुकी है, जो अंटार्कटिका के पूरे महाद्वीप से अधिक है।

भूमि क्षरण चिंता का विषय क्यों है?

मानव एवं पारिस्थितिक तंत्र पर भूमि क्षरण का दुष्प्रभाव:

- भूमि क्षरण पृथ्वी के चारों ओर मनुष्यों और पारिस्थितिकी तंत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए:
  - ➢ यह खाद्य उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा को कम करके कुपोषण के जोखिम को बढ़ाता है।
  - ➢ यह जल और खाद्य जनित रोगों के प्रसार में योगदान देता है जो खराब स्वच्छता और स्वच्छ पानी की कमी के परिणामस्वरूप होते हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- यह मिट्टी के कटाव के कारण श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बन सकता है।

जल प्रणाली का प्रदूषण:

- भूमि क्षरण के कारण समुद्री और मीठे पानी की प्रणालियाँ भी प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए, उर्वरक और कीटनाशकों को ले जाने वाली मिट्टी का क्षरण जल निकायों में बह जाता है, जिससे वहाँ रहने वाले जीव-जंतुओं और उन पर निर्भर स्थानीय समुदायों दोनों को नुकसान पहुँचता है।

जलवायु परिवर्तन में भी योगदान:

- भूमि क्षरण जलवायु परिवर्तन में भी योगदान देता है।
- उल्लेखनीय है कि दुनिया की मिट्टी सबसे बड़ी स्थलीय कार्बन सिंक है। जब भूमि का क्षरण होता है, तो मिट्टी का कार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ वायुमंडल में मुक्त हो सकता है।
- इससे ग्लोबल वार्मिंग और भी बढ़ सकती है।

वृक्षों एवं मिट्टी की कार्बन सिंक क्षमता पर दुष्प्रभाव:

- इस नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमि क्षरण ने पिछले दशक में पेड़ों और मिट्टी जैसे भूमि पारिस्थितिकी तंत्रों की मानव-जनित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता को 20% तक कम कर दिया है।

- पहले, ये पारिस्थितिकी तंत्र इस तरह के प्रदूषण का लगभग एक-तिहाई हिस्सा अवशोषित कर सकते थे।

भूमि क्षरण का कारण क्या है?

- **अस्थायी कृषि पद्धतियाँ:** रासायनिक इनपुट, कीटनाशकों और पानी के डायवर्जन का अत्यधिक उपयोग जैसी अस्थाई कृषि पद्धतियाँ भूमि क्षरण के सबसे प्रमुख कारण हैं। क्योंकि ऐसी प्रथाओं से वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव और प्रदूषण होता है।
- **जलवायु परिवर्तन:** भूमि क्षरण न केवल जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है बल्कि इससे प्रेरित भी होता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग ने भारी वर्षा की आवृत्ति, तीव्रता और मात्रा में वृद्धि और गर्मी के तनाव में वृद्धि करके भूमि क्षरण को और खराब कर दिया है।
- **तेजी से शहरीकरण:** अगला कारण तेजी से शहरीकरण है, जिसने हैबिटेट विनाश, प्रदूषण और जैव विविधता हानि में योगदान देकर भूमि क्षरण को तेज कर दिया है।

दुनिया कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?

- इस रिपोर्ट में दक्षिण एशिया, उत्तरी चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका में हाई प्लेन्स और कैलिफोर्निया और भूमध्य सागर के आस-पास जैसे शुष्क क्षेत्रों में भूमि क्षरण के कई हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। मानवता का एक तिहाई हिस्सा अब शुष्क भूमि पर रहता है, जिसमें अफ्रीका का तीन-चौथाई हिस्सा शामिल है।
- इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि भूमि क्षरण कम आय वाले देशों को असमान रूप से प्रभावित करता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQs

1. चर्चा में रहे 'ब्रिक्स देशों की 'डी-डॉलराइजेशन' योजना पर डोनाल्ड ट्रम्प की 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

   1. डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियां भारत के लिए विशेष रूप से चिंताजनक हैं, जो अमेरिका के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध बनाए रखता है।

   2. क्योंकि डी-डॉलराइजेशन भारत की आर्थिक नीति या रणनीति का हिस्सा रहा है।

   उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1

   (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों

   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

   Ans:(a)

2. ब्रिक्स समूह द्वारा अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) ब्रिक्स समूह अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के इच्छुक हैं।

   (b) डॉलर-प्रधान वित्तीय प्रणाली अमेरिका को प्रमुख आर्थिक लाभ देती है।

   (c) ब्रिक्स राष्ट्रों ने अमेरिका पर डॉलर को "हथियार" बनाने का आरोप लगाया है।

   (d) उपर्युक्त सभी कथन सही है।

   Ans:(d)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

3. भारत सरकार GDP की गणना के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से अद्यतन करना चाहता है। ऐसे में 'GDP के आधार वर्ष में संशोधन की आवश्यकता' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. GDP आधार वर्ष संशोधन सटीक आर्थिक डेटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप है।
2. यह क्रय शक्ति में बदलाव को समझने में मदद करता है और मुद्रास्फीति के लिए समायोजित विकास के आंकड़ों की गणना करने में सक्षम बनाता है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(c)

4. भारत सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की गणना के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से 2022-23 तक अद्यतन करने के परिवर्तन की देखरेख के लिए, किसकी अध्यक्षता में 26 सदस्यीय 'राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति' का गठन किया है।

(a) अरविन्द विरमानी

(b) बिस्वनाथ गोल्डर

(c) एन के सिंह

(d) बी वी आर सुब्रमण्यम

Ans:(b)

5. चर्चा में रहे भूमि क्षरण की वैश्विक चुनौती पर UNCCD की हालिया रिपोर्ट 'स्टेपिंग बैक फ्रॉम द प्रीसिपिस: ट्रांसफॉर्मिंग लैंड मैनेजमेंट टू स्टे इन द प्लेनेटरी बाउंड्री' के निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में हर साल दस लाख वर्ग किलोमीटर भूमि का क्षरण हो रहा है।
2. भूमि क्षरण ने पिछले दशक में पेड़ों और मिट्टी जैसे भूमि पारिस्थितिकी तंत्रों की मानव-जनित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता को 20% तक कम कर दिया है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(c)